

दया याचकिएँ

प्रलिमिस के लिये:

राष्ट्रपति, दया याचकिएँ, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, न्यायकि समीक्षा, उच्चतम न्यायालय (SC), क्षमादान शक्ति, मृत्युदंड, वधि आयोग, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21, प्रतिलिपन, वरिम/परहिर, दंडादेश का नलिंबन, लघुकरण, भारतीय न्यायपालकि

मेन्स के लिये:

दया याचकिएँ जारी करना

सरोतः इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के **राष्ट्रपति** ने एक पाकिस्तानी नागरिक की दया याचकिएँ को अस्वीकार कर दी जसे वर्ष 2000 में लाल कलि पर हुए आतंकी हमले के लिये मृत्युदंड दिया गया था।

दया याचकिएँ क्या हैं?

परचियः

- दया याचकिएँ एक औपचारिक अनुरोध है, यह अनुरोध कसी ऐसे व्यक्तजिसे मृत्युदंड या कारावास की सजा दी गई हो, द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए किया जाता है, जैसा भी मामला हो।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड कंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचकिएँ के बिचार का पालन किया जाता है।
- सभी को **जीवन का अधिकार** प्राप्त है। इसे भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **मौलिक अधिकार** के रूप में भी वर्णित किया गया है।
- नहिति धारणा: भारत में क्षमादान शक्तियों के पीछे धारणा इस मान्यता में नहिति है कि कोई भी न्यायकि प्रणाली अचूक नहीं है और संभावित न्यायकि तुट्टियों को सुधार हेतु एक तंत्र की आवश्यकता है।
 - न्यायकि तुट्टियों का सुधार: यह सुरक्षा उपाय न्याय की संभाविति तुट्टियों के विद्युद्ध सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 14 न्यायाधीशों ने भारत के राष्ट्रपति को अलग-अलग पत्रों में वर्ष 1990 के दशक के उन मामलों पर प्रकाश डाला, जिनमें न्यायालयों ने 15 व्यक्तियों को अनुचित तरीके से मृत्युदंड दिया था, हालाँकि उनमें से दो व्यक्तियों को बाद में मृत्युदंड दिया गया था।
 - सार्वजनिक वशिवास बनाए रखना: क्षमादान शक्ति का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय व्यवस्था में सामान्य जन के वशिवास को बनाए रखना है।
- संवैधानिकि ढाँचा:
 - भारत में संवैधानिकि ढाँचे के अनुसार, दया याचकिएँ के लिये राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतमि संवैधानिकि उपाय है। जब एक दोषी को वधिकि न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो दोषी भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 72** के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचकिएँ प्रस्तुत कर सकता है।
 - इसी प्रकार भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 161** के तहत राज्यों के **राज्यपालों** को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 72

- राष्ट्रपति के पास कसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए कसी भी व्यक्तिकी सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, वरिम देने या कम करने या सजा को नलिंबति करने, परहिर करने की शक्ति होगी।
- उन सभी मामलों में जहाँ सजा **कोर्ट मारशल** द्वारा दी गई हो;
- उन सभी मामलों में जहाँ सजा या कसी ऐसे मामले से संबंधिति कसी

अनुच्छेद 161

- इसके तहत कसी राज्य के राज्यपाल के पास कसी मामले से संबंधिति कसी भी कानून के खलिफ कसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए कसी भी व्यक्तिकी सजा को क्षमा, राहत देने, वरिम या छूट देने या नलिंबति करने, परहिर करने या लघुकरण शक्ति होगी जसिसे राज्य की शक्ति का वसितार होता है।
- वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कसी राज्य का

कानून के खलिक अपराध के लिये है, जसि पर संघ की कार्यकारी शक्ति का वसितार होता है;
■ सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया है।

राज्यपाल मृत्युदंड की सज्ञा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 वर्ष कारावास की सज्ञा काट चुका हो।

■ दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- दया याचिकाओं से निपटने के लिये कोई संवेदनकि लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायालय में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्तिया उसकी ओर से उसका संबंधी राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टपिण्डियों और सफिरशों के लिये भेज दिया जाता है।

■ दया याचिका दायर करने का आधार:

- दया या क्षमादान दोषी संदिध व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, उसकी पारविरकि वित्तीय स्थितियों (क्या वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं) के आधार पर दी जाती है।
 - शत्रुघ्न चौहान (2014)** भारत संघ (2014) जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संवेदन के अनुच्छेद 72 अथवा अनुच्छेद 161 के तहत दया मांगने का अधिकार एक संवेदनकि अधिकार है और यह कार्यपालिका के विकाय इच्छा पर निभिर नहीं है।

■ न्यायिक समीक्षा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों जैसे कभी राम बनाम भारत संघ, एप्रू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और केहर सहि बनाम भारत संघ में कहा है कि क्षमादान शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन सीमित आधार पर।
- न्यायालय ने क्षमादान शक्ति की **न्यायिक समीक्षा** के लिये निम्नलिखित प्रावधान बताए हैं:
 - शक्तियों का प्रयोग बनाम सोचे-समझे किया गया हो,
 - दुर्भावनापूर्ण आशय से किया गया हो, या
 - प्रासंगिक सामग्री को विचार से पृथक रखा गया हो।

दया याचिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं?

- बचन सहि बनाम पंजाब राज्य:** वर्ष 1980 में, उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की संवेदनकिता को बरकरार रखा, लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी स्थापित किये। न्यायालय ने कहा, "न्यायाधीशों को कभी भी खूनी (Bloodthirsty) नहीं होना चाहिये" और मृत्युदंड "दुरलभतम मामलों को छोड़कर" नहीं दिया जाना चाहिये, जब वैकल्पिक उपाय निर्विविद रूप से बंद हो गया हो, और सभी संभावित कम करने वाली प्रसिद्धियों पर विचार किया गया हो।
 - तब से लेकर अब तक न्यायालय ने कई फैसलों में "मृत्युदंड की सज्ञा मात्र अन्यान्यतम (The Rarest of The Rare)" मानक की पुष्टि की है।
- मार राम बनाम भारत संघ (1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रप्रिष्ठि की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- केहर सहि बनाम भारत संघ (1989):** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के दायरे की वसितार पूरक जाँच की थी।
 - केहर सहि मामले में, न्यायालय ने कहा कि दोषी को दया याचिका पर मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- शत्रुघ्न चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014):** इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोषी याचिकाओं पर नियम लेने में अत्यधिक वलिंब के कारण न्यायालय मौत की सज्ञा को कम कर सकते हैं।
- वधिआयोग की रपोर्ट:** वर्ष 2015 में प्रकाशित 262वें वधिआयोग की रपोर्ट में "आतंकवाद से संबंधित अपराधों और युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिये" मौत की सज्ञा को "पूर्ण रूप से समाप्त" करने की सफिरशी की गई थी।

क्षमादान शक्ति के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

क्षमादान शक्ति के प्रकार	विवरण	उदाहरण
क्षमा	यह कानून अपराधी को अपराध से पूरी तरह मुक्त कर देता है, तथा उसकी दोषसादिधि और उससे संबंधित सभी दण्डों को समाप्त कर देता है।	राष्ट्रपति देशदरोह के अनुचित आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है।
प्रतलिंबन	कठोर दण्ड के स्थान पर सामान्य दण्ड दिया जाता है।	राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परविरति करता है।
वरिष्ठ/परहिर	सज्ञा की प्रकृति में प्रविरतन किये बाहर उसकी अवधिकम कर दी जाती है।	राज्यपाल दो वर्ष के कठोर कारावास की सज्ञा में से एक वर्ष की छूट प्रदान करता है।
दंडादेश का नलिंबन	कसी सज्ञा के निषिपादन को अस्थायी रूप से स्थगित कर देता है, सामान्यतः थोड़े समय के लिये।	राष्ट्रपति कसी सज्ञायाफ्ता कैदी को दया याचिका दायर करने के लिये समय देने हेतु छूट प्रदान करते हैं।
लघुकरण	यह वह राहत है, जो अधिक लम्बी अवधिके लिये होती है और प्रायः चकितिसीय कारणों से होती है।	राज्यपाल एक असाध्य रूप से बीमार कैदी को राहत प्रदान करता है ताकि वह अपने अंतमि दिन घर पर बता सके।

- | | |
|--|--|
| <p>1. वह केन्द्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।</p> <p>2. वह सजा-ए-मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे।</p> <p>3. वह कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है।</p> | <p>1. वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है।</p> <p>2. वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, तो भी उसे राज्यपाल की बजाए राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है।</p> <p>3. उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।</p> |
|--|--|

अन्य देशों के कानून क्या प्रावधान करते हैं?

- **अमेरिका:** अमेरिका का संवधान राष्ट्रपति को महाभयोग के मामलों के अतिरिक्त संघीय कानून के तहत अपराधों के लिये छूट या क्षमा प्रदान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि राज्य के कानून के उल्लंघन के मामलों में, यह शक्ति राज्य के संबंधित राज्यपाल को दी गई है।
- **UK:** UK में, संवेधानकि प्रमुख, मंत्रसितरीय सलाह पर अपराधों के लिये क्षमा या राहत दे सकता है।
- **कनाडा:** आपराधिक राकिंड अधनियम के तहत राष्ट्रीय पैरोल बोर्ड को ऐसी राहत देने का अधिकार है।

निष्कर्ष

- आगे बढ़ने का मार्ग संतुलन बनाने में नहिति है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले उपाय, जैसे याचिकाओं पर विचार करने हेतु स्पष्ट दशा-निर्देश और नियन्य के लिये एक निश्चित समय-सीमा, जनता का विश्वास बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दया याचिका आवेदकों के लिये कानूनी प्रतनिधित्व सुनिश्चित करने से प्रक्रिया मजबूत होगी।
- अंततः: दया याचिका प्रणाली भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। इसकी विशेषताओं को स्वीकार करके तथा इसकी कमियों को दूर करके, भारत इस असाधारण शक्ति का अधिक मानवीय और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

टृष्णा भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. मृत्युदंड के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के प्रयोग से संबंधित महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????????????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी कसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपतिशासन अधिकारिता करने के लिये रपिरेट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्तिकरना
3. राज्य विधानसभा द्वारा पारित कल्पित विधियों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

?/?/?/?/?

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विचन कीजिय। विधायिका के समक्ष रखे बना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विचना कीजिय। (2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mercy-petition-2>

